Fiscal Policy & its objectives

राजकोषीय नीति एवं इसके उद्देश्य

classical economist के अनुसार बजट को बजट ही स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का सिद्धांत प्रचलित होती है। इस समय सरकारी हस्तक्षेप को अस्वीकार कर महत्व था और सरकारी हस्तक्षेप को अस्वीकार कर नहीं गया था।

1930 की विश्वव्यापी मंदी के समय राजकोषीय नीति में परिवर्तन आने लगा। इस नीति का उपयोग आर्थिक स्थिरता, कीमत नियन्त्रण, बेरोजगारी को दूर करने तथा आर्थिक विकास के लिए किया जाने लगा। अर्थव्यवस्था में सर्वोत्तम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजकोषीय नीति व्यय, ऋण, कर, आय, हीनार्थ प्रबन्धन आदि की समुचित व्यवस्था करती है।

classical economists के अनुसार अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार रहता है, कभी भी अति-उत्पादन की समस्या नहीं होती है। लेकिन विश्वव्यापी मंदी के बाद राजकोषीय नीति का उपयोग बेरोजगारी व अति-उत्पादन की समस्या दूर करने के लिए, उच्च रोजगार, कीमत में स्थिरता, विदेशी व्यापार में संतुलन एवं आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए किया जाने लगा। राजकोषीय नीति के निम्नलिखित उद्देश्य है –

1 Fiscal Policy and Employment

विश्वव्यापी मंदी के बाद Keyns ने रोजगार का सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसे प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धान्त भी कहते है। Keyns के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग दो बातों पर निर्भर करता है उपभोग एवं विनियोग। उपभोग को Keyns ने दीर्घकाल में स्थिर माना। लेकिन विनियोग दो बातों पर निर्भर करती है MEC और Rate

of Interest | MEC भी दीर्घकाल में स्थिर रहते है। क्योंकि ये मनोविज्ञान पर निर्भर करते है। अंत में ब्याज दर ही विनियोग को प्रभावित करता है। ब्याज की दर में कमी लाकर विनियोग को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ब्याज दर में कमी के समय अगर विनियोगकर्ता को सम्भावित लाभ में कमी होने का एहसास हो तो वह कितना भी ब्याज दर कम किया जाए निवेश नहीं बढ़ेगा। तब सरकारी व्यय ही एकमात्र विकल्प होता है जिससे बेरोजगारी दूर किया जाए। सार्वजनिक निर्माण कार्य के द्वारा सरकार बेरोजगारी दूर कर सकती है। इसप्रकार राजकोषिय नीति के निम्न उपायों द्वारा रोजगार प्राप्त किया जा सकता है

उपाय

(a) उपभोग प्रवृति बढ़ाने के उपाय

To increase Propensity to consume

केन्स के अनुसार धनियों की अपेक्षा निर्धनों की उपभोग प्रवृति अधिक होती है। अतः उनकी आय में वृद्धि की जानी चाहिए। यह तभी सम्भव है जब धनियों पर उस सीमा तक करारोपण किया जाय जहाँ तक उनकी काम करने व बचत करने की इच्छा या योग्यता पर बुरा प्रभाव न पड़े तथा उस आय को निर्धनों की ओर इसप्रकार हस्तान्तरित किया जाय कि उसका प्रत्यक्ष लाभ निर्धनों को मिले।

(b) निवेश में वृद्धि (To increase Investment)

निवेश दो प्रकार का होता है व्यक्तिगत एवं सरकारी निवेश। व्यक्तिगत निवेश बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयासों से विनियोग के लिए उद्यमियों को आकर्षित करना और स्वदेश में विदेशी पूंजीपतियों को आमंत्रित करके

2. Fiscal Policy and Economic Growth

आर्थिक विकास की समस्या विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक होती है। अतः राजकोषीय नीति के द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा जा सकता है। जो नीतियाँ निम्नलिखित है।

(a) राष्ट्रीय आय में वृद्धि (Increase in National Income)

विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय दोनों का ही स्तर काफी कम होता है। आय स्तर को बढ़ाने के लिए राजकोषीय नीति निम्न प्रकार से सहायक होती है-

1. Effective tax system

प्रभावशाली कर प्रणाली के द्वारा आय प्राप्त करके उस आय को सामाजिक कल्याण के कार्यों में व्यय किया जाना चाहिए। जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी।

2. Effective Economic Policies

उचित आर्थिक नीतियों का संचालन इसप्रकार होना चाहिए कि विनियोग कर्ताओं को नये नये विनियोगों की ओर आकर्षित किया जा सके तथा आयात व निर्यात नीति को लोचपूर्ण बनाकर नये उद्योगपतियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आकर्षित किया जा सके।

3. Increase in Effective Demand

~~उचित आर्थिक नीतियों का संचालन~~ सार्वजनिक ऋण एंव करों को ऐसी दिशा दी जानी चाहिए जिससे Effective demand में वृद्धि हो सके।

4. To maintain ability and Desire of working capacity

राजकोषीय नीति का उद्देश्य इसप्रकार से निर्धारित किया जाय कि लोगों की बचत करने व काम करने की योग्यता पर बुरा प्रभाव न पड़े।

निवेश व उत्पादन के स्तर में वृद्धि करता।

सरकारी निवेश को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से ऐसी योजनाओं पर निवेश होगा जो रोजगार मूलक तथा दीर्घकाल तक चलनेवाली होगी जैसे - नदी - घाटी योजना, रेल - सड़क यातायात, पुल आदि। सरकारी निवेश मुख्य रूप से असामान्य ज्यादा जरूरी हो जाता है जब मंदी के समय उद्योगपतियों को हानि होती है जिससे वे ~~अत्पादन~~ उत्पादन नहीं बढ़ा पाते।

(c) घाटे का व्यय (Deficit Finance)

जब सरकारी ऋण एवं करारोपण से उपभोग में कमी आने लगती है तो सरकार अपने व्यय को घाटे की वित्त व्यवस्था से भी पूरी कर सकती है। यदि सरकार नोट छापकर व्यय करती है तो इस क्रिया से भी रोजगार में वृद्धि होगी।

(d) व्यय के बिना घाटा (expenditure Without Deficit)

कभी कभी सरकार व्यय में वृद्धि किये बिना Effective demand में वृद्धि करके ~~के लिए~~ रोजगार में वृद्धि कर सकती है। इसके लिए सरकार कर की दरों में कमी करके लोगों की आय में वृद्धि कर सकती है। जिससे उपभोग एवं रोजगार में वृद्धि होगी।

(e) घाटे के बिना व्यय (Deficit Without expenditure)

बिना घाटे के व्यय में वृद्धि करना "सन्तुलित बजट गुणक" कहलाता है। इस नीति के अन्तर्गत सरकारी व्यय में उतनी ही वृद्धि की जाती है जितनी कि करों की राशि में वृद्धि की गई हो। सरकार करारोपण से प्राप्त सम्पूर्ण आय को व्यय कर देती है।